construction of drains and service roads, at the same level as that of plots on either side.

In many places, there are complaints about the 'high' level at which drains and service roads are being built. The people are afraid that their land and buildings would get flooded in case of a heavy rainfall. So, there is a need to ensure that the scientific norms are assiduously adhered to, in the construction of service roads and drains. There is a need to urgently build sufficient number of overbridges at the required locations so that the fundamental right of the citizens to travel freely is upheld. I urge upon the Government to look into it. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by hon. Member, Dr. V. Sivadasan: Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Haris Beeran (Kerala), and Shri Sandosh Kumar P (Kerala).

Demand for compensation for unorganized workers through quasi-judicial mechanism

DR. AJEET MADHAVRAO GOPCHADE (Maharashtra): Respected Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. हमारे देश में एक बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये श्रमिक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जैसे निर्माण, कृषि, सेवाएं एवं घरेलू कामकाज और अक्सर कारखानों और राज्यों के बीच स्थानांतरित होते रहते हैं। असंगठित श्रमिकों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अक्सर असुरक्षित कार्य परिस्थितियों का सामना करते हैं। ये श्रमिक बिना किसी सुरक्षा उपायों के काम करते हैं, जिससे उन्हें गंभीर चोट या यहाँ तक कि मृत्यु का भी जोखिम होता है। कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में, इन श्रमिकों के परिवारों को आमतौर पर कारखाना मालिकों से अपर्याप्त मुआवजा प्राप्त होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन श्रमिकों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होती, जिससे वे अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पाते। इस स्थिति को सुधारने के लिए मेरा सुझाव है कि सरकार फैक्ट्री मालिकों को अर्ध-न्यायिक तंत्र के माध्यम से असंगठित श्रमिकों को मुआवजा देने का निर्देश दे। इससे न केवल श्रमिकों को उनके अधिकारों का संरक्षण मिलेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि उन्हें कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए उचित मुआवजा मिले। मैं प्रत्येक जिले में अर्ध-न्यायिक समितियों की स्थापना का सुझाव देता हूँ। इन समितियों में श्रमिक प्रतिनिधियों, कारखाना मालिकों और सरकारी अधिकारियों का समावेश होगा, ताकि सभी पक्षों की आवाज सुनी जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। मेरी सरकार से यह माँग है कि इस पर ध्यान दिया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by hon. Member, Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu) ,Dr. Sasmit Patra (Odisha) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

Demand for purchase of surplus rice in Chhattisgarh

श्रीमती फूलो देवी नेतम (छत्तीसगढ़): महोदय, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन जब भी धान की फसल तैयार होती है, किसानों की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों से इस साल 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। 108 लाख टन कस्टम मिलिंग से चावल बनेगा। इसमें 93 लाख टन केन्द्रीय पूल एवं 14.20 लाख टन राज्य पूल का है।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत केवल 70 लाख टन कस्टम मिलिंग चावल खरीदी की अनुमति दी गई है। ऐसी स्थिति में राज्य द्वारा धान की खरीद कम की जाएगी और सीधा नुकसान छत्तीसगढ़ के किसानों को होगा।

अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत चावल उपार्जन मात्रा 70 लाख टन में वृद्धि करते हुए सरप्लस चावल को खरीदा जाए, जिससे धान किसानों को राहत मिल सकेगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): The following hon. Members associated themselves with the Special Mention made by the hon. Member, Shrimati Phulo Devi Netam: Shri Ashok Singh (Madhya Pradesh), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Shri A.A. Rahim (Kerala), Shri M. Mohamed Abdulla (Tamil Nadu), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Dr. John Brittas (Kerala) and Shri Anil Kumar Yadav Mandadi (Telangana).

Concern over Issues being faced by migrant students/aspirants in India

SHRI KARTIKEYA SHARMA (Haryana): The coaching industry in India, vital for competitive exam preparation, generates an estimated revenue of Rs.58,088 crores per year and it is projected to reach Rs.1,33,995 crores by 2028. However, this success conceals challenges such as exorbitant fees, inadequate teaching standards and lack of personalized attention. Thousands of aspirants flock annually to Delhi, particularly Old Rajinder Nagar, Karol Bagh and North Campus, for UPSC and other coaching. Many are housed in private hostels and PGs, as Delhi University alone